ALL INDIA BANK EMPLOYEES' ASSOCIATION

Central Office: "PRABHAT NIVAS" Regn. No. 2037
Singapore Plaza, 164, Linghi Chetty Street, Chennai-600 001
Phone: 2535 1522 Web: www.aibea.in 98400 89920
e mail : chv.aibea@gmail.com & aibeahq@gmail.com

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय:- एक असफल प्रयोग?

1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में SBI के पांच सहयोगी बैंकों का विलय कर दिया गया। 1 अप्रैल 2019 को देना और विजय बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया, जबकि मेगा विलय में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया, सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय कर दिया गया, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया, और 1 अप्रैल, 2020 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय कर दिया गया। मार्च, 2017 तक सार्वजनिक क्षेत्र के 25 बैंक थे, जो अब घटकर 12 हो गए हैं।
वित्त मंत्री के शब्दों में जिस उद्देश्य से विलय को आगे बढ़ाया जा रहा था, वह था;

"अधिक राष्ट्रीय उपस्थिति और वैश्विक पहुंच के लिए"
"पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए बड़े पैमाने वाले बैंक"
"बढ़ी हुई क्षमता और बढ़े हुए ऋण देने वाले बड़े बैंक, अधिक वित्तीय क्षमता के आधार पर बड़े आकार के ऋण देने और प्रतिस्पर्धी संचालन करने की क्षमता बढ़ाकर समामेलित संस्थाओं को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे"
इस पृष्ठभूमि में, मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार मार्च, 2017 के बैंकिंग आंकड़ों की तुलना से पता चलता है।

2017 और 2021 के बीच बैंकों के रणनीतिक प्रोफाइल की तुलना

(राशि रूपए में)

शाखाएं	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	विदेशी बैंक	लघु वित्त बैंक	कुल
मार्च 2021 तक	90,480	36,024	22,201	880	4,863	1,54,448

% शेयर	58.60	23.30	14.40	0.60	3.10	100.00
मार्च 2017 तक	94,142	24,423	21,358	293	-	1,40,216
% शेयर	67.10	17.50	15.20	0.20	-	100.00
राशि में वृद्धि	- 3662	11,601	843	587	4,863	14232
वृद्धि प्रतिशत में	- 3.89	47.50	3.95	300.34	-	10.15

जमा	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	विदेशी बैंक	लघु वित्त बैंक	कुल
मार्च 2021 तक	94,59,987	46,23,903	5,10,898	7,60,932	87,774	154,43,494
% शेयर	61.30	29.90	3.30	4.90	0.60	100.00
मार्च 2017 तक	74,47,568	24,71,231	3,65,706	4,45,522	-	107,30,027
% शेयर	69.40	23.00	3.40	4.20	-	100.00
राशि में वृद्धि	20,12,419	21,52,672	1,45,192	3,15,410	87774	47,13,467
वृद्धि प्रतिशत में	27.02	87.11	39.70	70.80	-	43.93

अग्रिमों	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	विदेशी बैंक	लघु वित्त बैंक	कुल
मार्च 2021 तक	62,63,382	39,21,696	33,96,09	4,40,394	1,12,969	110,78,050
% शेयर	56.50	35.40	3.10	4.00	1.00	100.00
मार्च 2017 तक	52,04,930	21,27,062	2,29,704	3,56,714	-	79,18,410
% शेयर	65.70	26.90	2.90	4.50	-	100.00
राशि में वृद्धि	10,58,452	17,94,634	1,09,905	83,680	1,12,969	31,59,640
वृद्धि प्रतिशत में	20.34	84.37	47.85	23.46	-	39.90

कुल व्यवसाय	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	विदेशी बैंक	लघु वित्त बैंक	कुल
मार्च 2021 तक	157,23,369	85,45,599	8,50,507	12,01,326	2,00,743	265,21,544
% शेयर	59.20	32.20	3.20	4.50	0.90	100.00
मार्च 2017 तक	126,52,498	45,98,293	5,95,410	8,02,236	-	186,48,437
% शेयर	67.85	24.65	3.20	4.30	-	100.00
राशि में वृद्धि	30,70,871	39,47,306	2,55,097	3,99,090	2,00,743	78,73,107
वृद्धि प्रतिशत में	24.27	85.84	42.84	49.75	-	42.22

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

इस अवधि के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के शाखा नेटवर्क में 3,662 की कमी हुई है, जिसके विरुद्ध निजी क्षेत्र के बैंकों ने 11,601 शाखाएँ, लघु वित्त बैंक ने 4,863 शाखाएँ और विदेशी बैंकों ने 587 शाखाएँ खोली हैं।

बैंकों के विलय के परिणामस्वरूप, शाखाओं के युक्तिकरण के नाम पर, विलय की गई संस्थाओं ने अपनी शाखाएँ बंद कर दी हैं, जिनकी संख्या बहुत अधिक है क्योंकि शाखा नेटवर्क में यह कमी उन बैंकों द्वारा नई शाखाएँ खोलने के बाद की गई है।
अब, पहले दो विलय का निपटारा हो गया है। इस अवधि के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक के शाखा नेटवर्क में 836 की कमी की गई, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा की 1,062 शाखाओं द्वारा।

पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और केनरा बैंक के मामले में शाखा बंद करने की प्रक्रिया चल रही है इसलिए हमें मार्च 2022 के बाद ही वास्तविक तस्वीर मिलेगी। केवल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मेगा विलय में शामिल बैंकों के मामले में भारत, शाखा नेटवर्क अब तक 117 शाखाओं से कम हो गया है।
विलय के कारण सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्य कर्नाटक है, जहां कर्नाटक में बैंक की प्रमुख उपस्थिति जैसे स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, कॉर्पोरेशन बैंक और सिंडिकेट बैंक के विलय के बाद से 516 शाखाओं को बंद कर दिया गया है।
429 शाखाओं के साथ दूसरा सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद मराठवाड़ा (पूर्व निजाम राज्य) में प्रमुख उपस्थिति के साथ और मुंबई में महत्वपूर्ण उपस्थिति वाले देना बैंक का विलय कर दिया गया है।
इसके बाद 268 शाखाओं के साथ दिल्ली और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के विलय के कारण 248 शाखाओं के साथ पंजाब है।
इसके बाद गुजरात है जहां देना बैंक के विलय के कारण 200 शाखाएं बंद हुई हैं और केरल जहां स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के विलय के कारण 199 शाखाएं बंद हुई हैं।

हालांकि बैंकों ने लगभग सभी क्षेत्रों में इस अवधि के दौरान शाखाएं खोली हैं, लेकिन कुल प्रभाव शाखाओं में कमी है, जिसके मुकाबले इस अवधि के दौरान, निजी क्षेत्र के बैंकों ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा खाली किए गए स्थान पर कब्जा करके बड़े पैमाने पर विस्तार किया है जिस वजह से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के शाखा नेटवर्क में हिस्सेदारी में 8.50% की कमी हुई है जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी में 5.80%, लघु वित्त बैंक में 3.10% और विदेशी बैंकों में 0.40% की वृद्धि हुई है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में विकास दर 3.80% कम हुई है, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में यह 47.50% है और विदेशी बैंकों के मामले में यह 300% बढ़ी है।

इस प्रकार, बैंकों के विलय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए जगह कम कर दी है और निजी बैंकों के लिए जगह बढ़ा दी है। जब एआईबीईए ने बैंकों के विलय का विरोध किया, तो हमने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समेकन से निजी क्षेत्र के बैंकों के विस्तार को लाभ होगा और, वही हुआ है।

इसका सीधा असर इन बैंकों के कारोबार पर भी पड़ा है।

जमा धन के मामले में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की बाजार हिस्सेदारी 8.10% कम हो जाती है जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में यह 6% बढ़ जाती है।

क्रेडिट के मामले में भी ऐसा ही है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की बाजार हिस्सेदारी 9.20 प्रतिशत कम हो गयी है जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में यह 8.50% बढ़ गयी है।

जहां तक कुल कारोबार का सवाल है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की बाजार हिस्सेदारी में 8.60% की कमी हुई है, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी में 7.60% की वृद्धि हुई है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वृद्धि दर 24.27% है, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों की वृध्धि 85.84% है, क्योंकि मुख्यतः ऋण में, निजी क्षेत्र के बैंकों की 84.37% की वृद्धि हुई है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की केवल 20.34%।

डेटा स्व-व्याख्यात्मक है। विलय की प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपना बाजार हिस्सा काफी खो दिया है, जिसका अर्थ है कि उस हद तक बैंकों का औपचारिक रूप से निजीकरण किए बिना बैंकिंग व्यवसाय का निजीकरण कर दिया गया है।

इस प्रक्रिया में, बैंकिंग विचलित हो गई है, ग्राहकों को परेशान किया जा रहा है और कर्मचारी बाहर निकल गए हैं। इस प्रकार, बैंकिंग कर्मचारियों और ग्राहकों ने विलय की कीमत चुकाई है।

वह शब्दजाल जिसके साथ विलय किया गया था: "यह बैंकों को वैश्विक बैंकिंग स्तर का बनाने में और भारत और विश्व में कुशलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने में मदद करेगा", अंततः भ्रम साबित हुआ है।

इसका फायदा निजी क्षेत्र के बैंकों को मिला है। क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय करना सरकार का यही छिपा हुआ एजेंडा था?

विलय का विरोध करते हुए यूनियनें "मर्डर इज मर्डर" का लोकप्रिय नारा देती थीं।

जो दुर्भाग्य से सही साबित हुआ है।

अब, बैंक के निजीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए कम से कम सरकार को बैंकिंग, अर्थव्यवस्था और बड़े पैमाने पर लोगों के हित में अपने रुख पर फिर से विचार करना चाहिए!

सभी हितधारकों, शिक्षाविदों, बैंक अर्थशास्त्रियों आदि के साथ सूचित बहस के बाद भारत की राष्ट्रीय बैंकिंग नीति तैयार की जानी चाहिए।

डी आर तुलजापुरकर द्वारा संकलित दस्तावेज़
संयुक्त सचिव, एआईबीईए

सी.एच. वेंकटचलम,
महासचिव, एआईबीईए
द्वारा प्रकाशित